QUESTION

SelectionWay

Q10. Which of the following rights has NOT been interpreted as part of Article 21 by the Supreme Court?

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निम्नलिखित में से किस अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में नहीं की गई है?

IB ACIO 2025 / IB SA 2025

(a) Right to Marry / विवाह का अधिकार

(b) Right to Shelter / आश्रय का अधिकार

(c) Right to Vote / मतदान का अधिकार

(d) Right to Privacy / निजता का अधिकार

SOLUTION

✅ Correct Answer: (c) Right to Vote / मतदान का अधिकार

- **Article 21 guarantees the Right to Life and Personal Liberty./** अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

- **Over time, the Supreme Court has expanded its scope to include:/** समय के साथ, सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दायरे को बढ़ाकर इनमें शामिल किया है:
  1. **Right to Privacy (Puttaswamy Case, 2017)/** गोपनीयता का अधिकार (पुट्टस्वामी मामला, 2017)
  2. **Right to Shelter/** आवास का अधिकार
  3. **Right to Marry and Live with Dignity/** विवाह करने और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार

SOLUTION

- However, Right to Vote is a statutory right, not a fundamental right./ हालाँकि, मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं।
- It arises from the Representation of the People Act, 1951, not from Article 21./ यह अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से प्राप्त होता है, अनुच्छेद 21 से नहीं।
- Article 21 interpreted liberally in Maneka Gandhi v. Union of India (1978)./ अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ' (1978) मामले में की गई।
- Described as the "heart of Fundamental Rights."/ इसे "मौलिक अधिकारों का हृदय" कहा गया है।

QUESTION

Q11. Right to Education was added as a Fundamental Right in the Indian Constitution in ____.

भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में ____ में जोड़ा गया था।

SSC CPO-SI 23/11/2020 Shift-I, SSC MTS/Havaldar 06/07/2022 Shift-II

(a) 2004
(b) 1997
(c) 1986
(d) 2002

SOLUTION

✅ Correct Answer: (d) 2002

- The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 added Article 21A, making the Right to Education a Fundamental Right./ 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिससे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया।

- Ensures free and compulsory education for children aged 6 to 14 years./ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।

SOLUTION

- Implemented through the Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE), 2009./ इसे बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के माध्यम से लागू किया गया।
- The right is derived from the Directive Principle (Article 45)./ यह अधिकार नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 45) से व्युत्पन्न है।
- Education before 2002 was only a Directive Principle, not a right./ 2002 से पहले शिक्षा केवल एक नीति निदेशक तत्व थी, अधिकार नहीं।

QUESTION

Q12. The Preventive Detention Act curtailed which right?

निवारक निरोध अधिनियम ने किस अधिकार को सीमित किया था?

SSC CGL Tier-I – 10/09/2016, 4:15 PM

(a) Right to Freedom / स्वतंत्रता का अधिकार

(b) Right to Equality / समानता का अधिकार

(c) Right to Property / संपत्ति का अधिकार

(d) Educational Rights / शैक्षिक अधिकार

SelectionWay

SOLUTION

✅ Correct Answer: (a) Right to Freedom / स्वतंत्रता का अधिकार

- The Preventive Detention Act, 1950 restricted the Right to Freedom (Article 19 & 22)./ 1950 का प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट (निवारक निरोध अधिनियम) ने स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19 और 22) पर प्रतिबंध लगाए।

- It allows the government to detain a person if it believes that the person may act against public order or national security./ यह सरकार को अधिकार देता है कि यदि किसी व्यक्ति से लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो उसे निरुद्ध किया जा सकता है।

SOLUTION

- **Detention is done before any crime is committed — a preventive measure./** यह निरोध किसी अपराध के घटित होने से पहले किया जाता है — एक निवारक उपाय के रूप में।

- **Articles 20 & 22 – Quick Summary (Protection of Rights in Criminal Cases & Detention)/** अनुच्छेद 20 और 22 – संक्षेप सारांश (आपराधिक मामलों और निरोध में अधिकारों की सुरक्षा)

- **Article 20 – Protection in Respect of Conviction for Offences/** अनुच्छेद 20 – अपराधों के लिए दंड से संबंधित संरक्षण

SOLUTION

- Provides safeguards to accused persons in criminal cases./ यह आपराधिक मामलों में आरोपियों को संरक्षण प्रदान करता है।

(1) No ex-post facto law/ पूर्वव्यापी कानून नहीं:

- No person can be punished for an act that was not an offence when committed./ किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था।

(2) No double jeopardy/ दोहरे दंड का निषेध:

- No person shall be prosecuted or punished twice for the same offence./ किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार अभियुक्त या दंडित नहीं किया जा सकता।

SOLUTION

(3) No self-incrimination/ आत्म-अभियोग का निषेध:

- No person can be forced to testify against themselves./ किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
- Applies to: Criminal offences only, not civil cases./ लागू होता है: केवल आपराधिक अपराधों पर, नागरिक मामलों पर नहीं।
- Cannot be suspended even during Emergency./ यह अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
- Article 22 – Protection in Certain Cases of Arrest and Detention/ अनुच्छेद 22 – गिरफ्तारी और निरोध के कुछ मामलों में संरक्षण

SOLUTION

- Gives rights to persons arrested under ordinary law and rules for preventive detention./ यह साधारण कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों और निवारक निरोध के मामलों में अधिकार प्रदान करता है।

For ordinary arrest/ साधारण गिरफ्तारी के लिए:

- Must be informed of the reason for arrest./ गिरफ्तारी के कारण की सूचना दी जानी चाहिए।
- Has the right to consult a lawyer./ वकील से परामर्श करने का अधिकार है।
- Must be produced before a magistrate within 24 hours./ गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- No detention beyond 24 hours without judicial approval./ न्यायिक स्वीकृति के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक निरुद्ध नहीं किया जा सकता।

SOLUTION

Preventive detention provisions/ निवारक निरोध के प्रावधान:

- Allows detention before an offence is committed (to prevent threats to law & order)./ अपराध घटित होने से पहले ही निरोध की अनुमति देता है (कानून और व्यवस्था बनाए रखने हेतु)।
- Maximum detention: 3 months; can be extended up to 12 months with approval./ अधिकतम निरोध अवधि: 3 महीने; स्वीकृति मिलने पर 12 महीने तक बढ़ाई जा सकती है।
- Laws like National Security Act (NSA) use this provision./ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) जैसे कानून इस प्रावधान का उपयोग करते हैं।

QUESTION

Q13. Which one of the following pairs is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है?

U.P.P.C.S. Mains 2015

(a) Prohibition of traffic in human beings and forced labour – Article 23 / मानव तस्करी और बंधुआ मज़दूरी का निषेध – अनुच्छेद 23

(b) Protection of interests of minorities – Article 29 / अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण – अनुच्छेद 29

(c) Right to constitutional remedies – Article 32 / संवैधानिक उपचार का अधिकार – अनुच्छेद 32

(d) Right of minorities to establish and administer educational institutions – Article 31 / अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित व संचालित करने का अधिकार – अनुच्छेद 31

Art. 30

SOLUTION

✅ Correct Answer: (d) Right of minorities to establish and administer educational institutions – Article 31 / अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित व संचालित करने का अधिकार – अनुच्छेद 31

- Article 23 – Prohibition of Human Trafficking and Forced Labour/ अनुच्छेद 23 – मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध
- Bans exploitation in any form — human trafficking, begari (forced labour), or bonded labour./ किसी भी प्रकार के शोषण — मानव तस्करी, बेगारी (जबर्दस्ती श्रम) या बंधुआ मजदूरी — पर प्रतिबंध लगाता है।
- Applies to State and private individuals./ यह राज्य तथा निजी व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है।

SOLUTION

- Punishable by law under Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976./ बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत दंडनीय अपराध है।

- Exception: The State can impose compulsory service for public purposes (like national service or disaster relief)./ अपवाद: राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों (जैसे राष्ट्रीय सेवा या आपदा राहत) के लिए अनिवार्य सेवा लगा सकता है।

- Ensures human dignity and freedom of labour./ यह मानव गरिमा और श्रम की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

SOLUTION

Article 24 – Prohibition of Child Labour/ बाल श्रम का निषेध

- Prohibits employment of children below 14 years in factories, mines, or hazardous work./ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक कार्य में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाता है।

- Protects children's health, education, and development./ यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की रक्षा करता है।

- Implemented through/ निम्नलिखित कानूनों के माध्यम से लागू किया गया है:
  - ✓ Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986/ बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
  - ✓ Right to Education Act, 2009 (Article 21A)/ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अनुच्छेद 21A)
- Violation = punishable offence under labour laws./ उल्लंघन श्रम कानूनों के तहत दंडनीय अपराध है।

QUESTION

Q14. Which of the following rights is guaranteed in Article 25 of the Constitution?
संविधान के अनुच्छेद 25 में कौन-सा अधिकार सुनिश्चित किया गया है?

SSC MTS 08/08/2019 Shift-II,
SSC CGL Tier-I – 21/07/2023 Shift-II

(a) Right to religious freedom / धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
(b) Right to equality / समानता का अधिकार
(c) Cultural and educational rights / सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
(d) Right to constitutional remedies / संवैधानिक उपचार का अधिकार

14-18

29-30

32

SOLUTION

✅ Correct Answer: (a) Right to religious freedom / धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- **Article 25 – Freedom of Conscience and Free Profession, Practice, and Propagation of Religion/** अनुच्छेद 25 – अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र रूप से अंगीकरण, पालन तथा प्रचार का अधिकार
- **Guarantees freedom to profess, practice, and propagate any religion./** किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- **Applies to all persons (citizens and foreigners)./** यह सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों) पर लागू होता है।

SOLUTION

25-28

Article 26 – Freedom to Manage Religious Affairs
अनुच्छेद 26 – धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

a) To establish and maintain institutions for religious and charitable purposes./ धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार।

b) To manage its own affairs in matters of religion./ धर्म से संबंधित अपने कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार।

c) To own and acquire movable and immovable property./ चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व रखने और अधिग्रहण करने का अधिकार।

d) To administer such property in accordance with law./ ऐसी संपत्ति का प्रबंधन कानून के अनुसार करने का अधिकार।

SOLUTION

Article 27 – Freedom from Taxation for Promotion of Religion/ धर्म के प्रचार के लिए कर से मुक्ति

- No person shall be forced to pay taxes for the promotion or maintenance of any religion./ किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के प्रचार या पालन के लिए कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

- Keeps the State secular and neutral in religious matters./ यह राज्य को धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक मामलों में निष्पक्ष बनाए रखता है।

SOLUTION

Article 28 - Freedom as to Attendance at Religious Instruction/ धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता

- No religious instruction in wholly State-funded institutions./ पूर्णतः राज्य वित्तपोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
- Permitted in institutions managed by trusts or voluntarily attended./ ट्रस्ट द्वारा संचालित या स्वेच्छा से भाग लेने वाले संस्थानों में इसकी अनुमति है।
- Protects students' freedom of conscience./ यह विद्यार्थियों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

QUESTION

Q15. Which constitutional article ensures the protection of the cultural and educational rights of minorities?

कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है?

SSC Phase XIII – 25/07/2025 Shift-1

(a) Article 29 / अनुच्छेद 29

(b) Article 32 / अनुच्छेद 32

(c) Article 15 / अनुच्छेद 15

(d) Article 25 / अनुच्छेद 25

SOLUTION

1992

Muslim Jain Parsi
Sikh Bauddha
Christian

✅ Correct Answer: (a) Article 29 / अनुच्छेद 29

- Article 29 guarantees the Right to conserve language, script, and culture of any section of citizens./ अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है।
- It protects both religious and linguistic minorities./ यह धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार की अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है।
- Ensures that no citizen shall be denied admission to state institutions based on religion, race, caste, or language./ यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर राज्य संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
- Forms part of Cultural and Educational Rights (Articles 29–30)./ यह सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों (अनुच्छेद 29–30) का हिस्सा है।

Is "Minority" defined in our Constitution?

QUESTION

Q16. All minorities shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice on the basis of religion or language. Which Article of the Indian Constitution guarantees this right?

सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है?

SSC CHSL – 10/06/2022 Shift-I

(a) Article 28 / अनुच्छेद 28
(b) Article 36 / अनुच्छेद 36
(c) Article 30 / अनुच्छेद 30
(d) Article 25 / अनुच्छेद 25

Art 29 → Welfare of Minority

Art 30 → Est. of Religion Educational Inst.

SOLUTION

✅ Correct Answer: (c) Article 30 / अनुच्छेद 30

- Article 30(1) provides minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice./ अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है।
- Applies to both religious and linguistic minorities./ यह धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार की अल्पसंख्यकों पर लागू होता है।
- The State cannot discriminate in granting aid to such institutions./ राज्य इन संस्थानों को सहायता प्रदान करने में भेदभाव नहीं कर सकता।
- Ensures freedom to preserve culture and education./ यह संस्कृति और शिक्षा को संरक्षित रखने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

QUESTION

Q17. Which of the following was removed from the list of Fundamental Rights?

निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था?

SSC CGL 2025

(a) Right to Equality / समानता का अधिकार

(b) Right to Property / संपत्ति का अधिकार

(c) Right to Freedom / स्वतंत्रता का अधिकार

(d) Right against Exploitation / शोषण के विरुद्ध अधिकार

Art 31 → Art 300 (A)

44th Amend.

1978

SOLUTION

✅ Correct Answer: (b) Right to Property / संपत्ति का अधिकार

- The Right to Property (Article 19(1)(f) & Article 31) was removed from Fundamental Rights by the 44th Amendment Act, 1978./ संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31) को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया।
- It is now a legal right under Article 300A (Part XII)./ अब यह अनुच्छेद 300A (भाग XII) के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार है।
- Purpose: To enable land reforms and equitable distribution of property./ उद्देश्य: भूमि सुधारों को लागू करना और संपत्ति का समान वितरण सुनिश्चित करना।
- Prevented property disputes from blocking social welfare policies./ इससे संपत्ति से संबंधित विवादों को सामाजिक कल्याण नीतियों के मार्ग में बाधा बनने से रोका गया।

QUESTION

Q18. Which Article of the Constitution confers the right to constitutional remedies, and how is it linked to Fundamental Rights?

संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, और यह मौलिक अधिकारों से कैसे जुड़ा है?

SSC CGL 2025 / IB ACIO 2025

(a) Article 32: it is called the "heart and soul" of the Constitution / अनुच्छेद 32: इसे संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा जाता है

(b) Article 226: it is a protective mechanism for Directive Principles / अनुच्छेद 226: यह नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र है

(c) Article 21: it deals with personal liberty only / अनुच्छेद 21; यह केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है

(d) Article 14: it ensures equality before law / अनुच्छेद 14; यह कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है

SelectionWay

SOLUTION

✅ Correct Answer: (a) Article 32; it is called the "heart and soul" of the Constitution / अनुच्छेद 32: इसे संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ कहा जाता है

- Article 32 gives citizens the right to approach the Supreme Court for the enforcement of Fundamental Rights./ अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है।

- Described by Dr. B.R. Ambedkar as the “heart and soul of the Constitution.”/ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इसे “संविधान का हृदय और आत्मा” कहा था।

- Supreme Court can issue five types of writs: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, and Quo Warranto./ सर्वोच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा।

Five Writs of the Supreme Court (Under Article 32)
सर्वोच्च न्यायालय की पाँच रिटें (अनुच्छेद 32 के अंतर्गत)

Habeas Corpus ("Produce the Body")
बंदी प्रत्यक्षीकरण ("शरीर प्रस्तुत करो")

- Issued to release a person who is illegally detained./ किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किए जाने पर उसकी रिहाई के लिए जारी की जाती है।
- Protects personal liberty./ यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है।
- Example: If someone is arrested without legal reason, court orders the authority to produce the person before it./ उदाहरण : यदि किसी व्यक्ति को बिना कानूनी कारण के गिरफ्तार किया गया है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को प्रस्तुत करने का आदेश देता है।

SOLUTION

Mandamus ("We Command")
परमादेश ("हम आदेश देते हैं")

- Issued to a public official or authority to perform a duty they have failed to do./ यह किसी सार्वजनिक अधिकारी या प्राधिकरण को वह कर्तव्य पूरा करने का आदेश देती है, जिसे उन्होंने नहीं किया।
- Not issued against:/ यह निम्नलिखित के विरुद्ध जारी नहीं की जाती:
    1. The President or Governors, / राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध नहीं
    2. Private individuals. / निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं

SOLUTION

Prohibition ("To Forbid")
निषेध ("निषेध करना")

- **Issued by a higher court to a lower court or tribunal,/** यह उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है,

- **To stop it from proceeding in a case beyond its jurisdiction./** जब वह अपनी अधिकार-सीमा से बाहर किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो।

SOLUTION

Certiorari ("To Be Certified")
उत्प्रेषण ("प्रमाणित करने हेतु")

- Issued by a higher court to quash the order or judgment of a lower court or tribunal made without jurisdiction or in violation of law./ यह उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के उस आदेश को रद्द करने हेतु जारी की जाती है जो अधिकार-क्षेत्र से बाहर या कानून के उल्लंघन में दिया गया हो।
- Used for judicial correction./ यह न्यायिक सुधार के लिए प्रयुक्त होती है।

SOLUTION

Quo Warranto ("By What Authority")
अधिकार पृच्छा ("किस अधिकार से")

- Issued to question the legal validity of a person's holding of a public office./ यह किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद धारण करने की वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए जारी की जाती है।
- Prevents usurpation of public position without legal authority./ यह बिना वैध अधिकार के सार्वजनिक पद पर कब्जा करने से रोकती है।

SOLUTION

32

- **Ensures judicial protection against violation of rights./** यह अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायिक संरक्षण सुनिश्चित करती है।

- **Article 226 gives similar power to High Courts./** अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को समान अधिकार प्रदान करता है।

- **Fundamental Rights to Only Citizens: Articles 15, 16, 19, 29(1), and 30(1)./** केवल नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29(1) और 30(1)।